दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वार्षिकी

2019

पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स
पर बिंदुवार पुनरावलोकन

दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
(Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक परीक्षा)
(19 बुकलेट्स) ₹10,000/-

सामान्य अध्ययन
(मुख्य परीक्षा)
(26 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रारंभिक परीक्षा)
(27 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(31 बुकलेट्स) ₹15,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(39 बुकलेट्स) ₹17,500/-

हिन्दी साहित्य
(वैकल्पिक विषय)
₹7,000/-

इतिहास (वैकल्पिक विषय)
₹7,000/-

दर्शन शास्त्र (वैकल्पिक विषय)
₹5,000/-

For UPSC CSE (in English Medium)

Self Learning Modules

Students may opt for following modules

- Prelims (18 GS + 3 CSAT Booklets) ₹10000/-
- Mains (18 GS Booklets) ₹11000/-
- Prelims + Mains (36 GS + 3 CSAT Booklets) ₹15000/-

Offer

- *Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine with every module*
- *Free Test Series worth ₹ 6,000 for UPSC CSE Prelims 2019 with Prelims+Mains module*
- *Flat 50% discount on Test Series worth ₹ 6,000 for UPSC CSE Prelims 2019 with Prelims/Mains modules*

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

वार्षिकी
2019

दृष्टि पब्लिकेशन्स
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 87501 87501, 011-47532596
Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
booksteam@groupdrishti.com

संस्करण- जनवरी 2019

मूल्य : ₹ 200

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © **कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

जैसा कि आप जानते हैं कि दृष्टि पब्लिकेशन्स द्वारा पिछले दो वर्षों से 'वार्षिकी' का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें हम विगत वर्ष के घटनाक्रम में से महत्त्वपूर्ण व परीक्षोपयोगी मुद्दों का वार्षिक संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक वर्ष के करेंट अफेयर्स को पुस्तक रूप देने का यह हमारा तीसरा प्रयास है। हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि विगत वर्षों के दौरान आई.ए.एस., पी.सी.एस. सहित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न हमारी पुस्तक की परिधि में थे। यही कारण था कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने न केवल इसे हाथों-हाथ लिया, वरन् उनके द्वारा आगामी वर्ष के लिये भी करेंट अफेयर्स के इसी तरह के वार्षिक संकलन को प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। आपसे प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए हम आपके समक्ष पिछले 12 महीनों के घटनाक्रम को 'करेंट अफेयर्स टुडे-वार्षिकी 2019' के नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि आई.ए.एस., पी.सी.एस. सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 'करेंट अफेयर्स' का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस खंड की ठोस तैयारी के बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्तमान में करेंट अफेयर्स से संबंधित ढेर सारी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं, किंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से एक भी पुस्तक परीक्षा की बदलती प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं है। इन पुस्तकों में तथ्यात्मक अशुद्धियों के साथ गैर-परीक्षोपयोगी तथ्यों की भी भरमार है। अद्यतनता के अभाव एवं पुरानी घटनाओं के बार-बार दोहराव के कारण ये पुस्तकें अनुपयोगी तथ्यों का भंडारमात्र बन कर रह गई हैं जो विद्यार्थियों को तैयारी के दौरान दिग्भ्रमित कर देती हैं।

अभी आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा की चुनौती है। आई.ए.एस. सहित कई राज्यों की पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षाएँ होने वाली हैं। 'करेंट अफेयर्स टुडे-वार्षिकी 2019' इन चुनौतियों से पार पाने में आपके लिये प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी। यह पुस्तक मुख्यत: करेंट अफेयर्स की हमारी मासिक पत्रिका 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पिछले 12 महीनों के अंकों के आधार पर संकलित है, किंतु द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, साइंस रिपोर्टर, योजना, कुरुक्षेत्र आदि पत्र-पत्रिकाओं सहित कुछ वेबसाइट्स आदि से भी परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रियों को इस पुस्तक में संलग्न कर इसे नवीनता और समग्रता प्रदान की गई है। इससे निश्चय ही दृष्टि की मासिक पत्रिका के नियमित पाठकों को भी नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। यद्यपि एक वर्ष के करेंट अफेयर्स के विशाल भंडार से परीक्षोपयोगी तथ्यों को मात्र 256 पृष्ठों में प्रस्तुत करना सागर से मोती चुनने जैसा कार्य था, तथापि हमारी अनुभवी और दक्ष टीम ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

11 खंडों में विभाजित इस पुस्तक का प्रत्येक खंड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रत्येक खंड के पश्चात् विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गए संबद्ध खंड के प्रश्नों का संकलन भी दिया गया है जो कि आई.ए.एस., पी.सी.एस. सहित आगामी सभी परीक्षाओं के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। हमारा विश्वास है कि इन प्रश्नों को हल करने से न केवल पूरी पुस्तक का कम समय में रिवीज़न हो जाएगा, वरन् आप अपनी तैयारी का स्वमूल्यांकन भी कर सकेंगे। पुस्तक को त्रुटिहीन तथा अद्यतन बनाने के लिये इसका कई चरणों में सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। विद्यार्थियों को पढ़ते समय तथ्यों की दुरूहता की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिये उनका बिंदुवार प्रस्तुतीकरण किया गया है। विविध और खेल घटनाक्रम को नए और रोचक अंदाज़ में प्रस्तुत किया गया है जिससे अभ्यर्थियों को तथ्यों को आत्मसात् करने में आसानी होगी।

हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी तैयारी एवं सफलता में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मेरा निवेदन है कि आप इस पुस्तक को एक पाठक के साथ-साथ आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। **अगर आपको कोई भी कमी दिखे तो बेझिझक 8130392355 नंबर पर वाट्सएप मैसेज भेज दें।** आपकी टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर ही हम पुस्तक को और बेहतर व प्रामाणिक बना सकेंगे।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1.	संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम	1-35
2.	आर्थिक घटनाक्रम	36-66
3.	अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम	67-94
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	95-118
5.	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	119-156
6.	सुरक्षा	157-167
7.	रिपोर्ट एवं सूचकांक	168-183
8.	सामाजिक मुद्दे	184-197
9.	कला एवं संस्कृति	198-212
10.	खेल घटनाक्रम	213-222
11.	विविध	223-251

1 संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम
(Constitutional and Administrative Events)

पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव

चर्चा में क्यों?

11 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिज़ोरम की विधानसभाओं के लिये निर्वाचन संपन्न हुए।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिये राजपत्रित अधिसूचना 16 अक्तूबर को जारी हुई तथा 12 नवंबर को पहले चरण में मतदान किया गया। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिये अधिसूचना 26 अक्तूबर को जारी हुई तथा 20 नवंबर का दूसरे चरण में मतदान हुआ।
- मध्य प्रदेश व मिज़ोरम विधानसभा के निर्वाचन के लिये 2 नवंबर को अधिसूचना जारी की गई तथा 28 नवंबर को इन दोनों राज्यों में मतदान किया गया।
- राजस्थान व तेलंगाना की विधानसभाओं के लिये 12 नवंबर को अधिसूचना जारी की गई तथा 7 दिसंबर को इन राज्यों में मतदान संपन्न कराया गया।
- 11 दिसंबर, 2018 को पाँचों राज्य विधानसभाओं के लिये चुनाव परिणाम जारी किये गए।
- परिणामों में छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को 68 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें, जनता कॉन्ग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) को 5 सीटें तथा बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुईं।
- दिसंबर 2003 से दिसंबर 2018 के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉ. रमन सिंह ने अपने दल भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में बहुमत न जुटा पाने के बाद अपना पद त्याग दिया।
- मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से कॉन्ग्रेस को 114 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें तथा समाजवादी पार्टी को एक सीट प्राप्त हुई, इसके अतिरिक्त 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी विधानसभा के लिये चुने गए।
- मध्य प्रदेश में पिछले 13 वर्षों से (नवंबर 2005 से दिसंबर 2018) भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दल द्वारा बहुमत न जुटाए जा सकने के चलते अपना पद त्याग दिया।
- राजस्थान विधानसभा की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों के लिये मतदान हुआ क्योंकि निर्वाचन के पूर्व अलवर ज़िले की रामगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया था।
- 199 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को 99 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 सीटें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें तथा राष्ट्रीय लोक दल को 1 सीट प्राप्त हुई, इसके साथ ही 13 निर्दलीय प्रत्याशी भी निर्वाचित होकर विधानसभा पहुँचे।
- चुनाव परिणामों में अपने दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुमत प्राप्त न कर पाने के चलते दिसंबर 2013 से दिसंबर 2018 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने पद से त्यागपत्र दे दिया।
- तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों में से तेलंगाना राष्ट्र समिति को 88 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन को 7 सीटें, तेलुगू देशम पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 सीट मिली तथा 1 निर्दलीय प्रत्याशी भी निर्वाचित हुआ।
- तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (जून 2014 से) के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा बहुमत प्राप्त कर लिये जाने के बाद वे पुनः मुख्यमंत्री बन गए।
- मिज़ोरम राज्य विधानसभा की कुल 40 सीटों में से मिज़ो नेशनल फ्रंट को 26, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को 5 तथा भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर विजय प्राप्त हुई, इसके साथ ही 8 निर्दलीय प्रत्याशी भी विजयी हुए।
- 2008 से मिज़ोरम के मुख्यमंत्री रहे श्री लाल थनहावाला के दल भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के बहुमत तक न पहुँचने के चलते उन्होंने 12 दिसंबर, 2018 को अपना त्यागपत्र दे दिया।

बांध सुरक्षा विधेयक 2018

चर्चा में क्यों?

- 12 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में केंद्र सरकार ने बांध सुरक्षा विधेयक 2018 प्रस्तुत किया।
- इस विधेयक में देश में बांधों की सुरक्षा, बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा देखभाल एवं दुर्घटना की रोकथाम संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

सामान्य परिचय	• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (2006 में संशोधित) के तहत किया गया। यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। • इसका गठन संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया है। • मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना व एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना इसका उद्देश्य है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। • इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है। यह आयोग उन्हीं मामलों की जाँच कर सकता है जिन्हें घटित हुए एक वर्ष से कम समय हुआ हो। • प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आयोग की संरचना तथा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति	आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किये जाते हैं- • एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, • एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; • एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; • 2 सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किये जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं, जो इस प्रकार से हैं- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, दोनों सदनों में विपक्षी नेता व केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं।
आयोग के कार्य	• मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करना। • जेलों एवं बंदीगृहों में जाकर वहाँ की स्थिति देखना व सुधार हेतु अनुशंसा करना। • मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते का प्रभावी क्रियान्वयन। • मानवाधिकार संरक्षण हेतु विधिक उपायों के प्रति जन-जागरूकता पैदा करना। • न्यायालयों में लंबित मानवाधिकारों, जैसे- हिंसा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करना। • मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना। ***जाँच के संबंध में कार्य*** गवाहों को अपने पास बुलाकर परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज़ को अपने समक्ष मंगवाना, न्यायालय के अभिलेख या रिकॉर्ड मंगा सकता है, शपथपत्र पर गवाही ले सकता है।
वेतन/कार्यकाल/पदमुक्ति	• अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र (जो पहले हो) तक होता है। • कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र/राज्य सरकार के अधीन किसी पद के योग्य नहीं। • वेतन, भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एवं अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के पश्चात् वेतन, भत्तों एवं सेवा-शर्तों आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं। • पागल, दिवालिया, कार्यकाल के दौरान किसी अन्य व्यवसाय में संलिप्त, शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ, अपराधी या सज़ायाफ्ता होने पर पदच्युत किया जा सकता है। • अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है लेकिन ऐसा करने से पहले वह उच्चतम न्यायालय में जाँच हेतु मामले को सौंपेगा, जाँच की पुष्टि होने पर पदमुक्त किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न

1. आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून, 2016 की 'संवैधानिक वैधता' को खारिज़ कर दिया।
   2. आयकर रिटर्न फाइल करने तथा पैन आवंटन के लिये आधार अनिवार्य होगा।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. राज्यसभा चुनाव में 'नोटा' के विकल्प का उपयोग नहीं किया जा सकता।
   2. नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम 'उत्तर प्रदेश' चुनाव में किया गया था।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. ओडिशा सरकार द्वारा 'विधान परिषद्' की स्थापना के लिये प्रस्ताव पारित किया गया है।
   2. विधान परिषद् के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति 'संसद' के पास है।
   3. राज्यपाल द्वारा विधान परिषद् में नामित सदस्यों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) केवल 1 और 2
   (d) उपर्युक्त सभी
4. हाल ही में किस समिति ने डेटा सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है?
   (a) बी.एन. श्रीकृष्णा समिति
   (b) रतन वत्तल समिति
   (c) एन.के. सिंह समिति
   (d) एम.बी. शाह समिति
5. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. संसद ने वर्ष 2002 में 'प्रतिस्पर्धा अधिनियम' बनाया था।
   2. केंद्रीय मंत्रिमंडल के हालिया निर्णय के अनुसार, आयोग में अब एक अध्यक्ष और मात्र तीन सदस्य होंगे।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2
6. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. इस योजना के तहत निवेश सीमा को ₹ 7.5 लाख से बढ़ाकर ₹ 15 लाख कर दिया गया है।
   2. इस योजना को जी.एस.टी. से छूट प्रदान की गई है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2
7. इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. इसमें घर खरीदने वालों को वित्तीय लेनदारों के रूप में पहचाने जाने का प्रावधान है।
   2. इसमें 'नियमित निर्णयों' के लिये न्यूनतम मतदान सीमा को 75 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत कर दिया गया है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2
8. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
   2. इसमें केवल एस.सी. एवं एस.टी. समुदाय के लोगों को लाभार्थी बनाया गया है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2
9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. पिछड़ा वर्ग (OBC) का उप-वर्गीकरण करना राज्यों के लिये अनिवार्य नहीं है।
   2. अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में उप-वर्गीकरण को अपना लिया गया है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2
10. सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में दिये गए फैसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
    1. मुख्य न्यायाधीश ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर' है।
    2. भूमि, पुलिस और पब्लिक आर्डर के मामलों को छोड़कर उप-राज्यपाल दिल्ली सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरमाला

1. (b)	2. (a)	3. (d)	4. (a)	5. (c)
6. (c)	7. (c)	8. (a)	9. (a)	10. (c)

2

आर्थिक घटनाक्रम
(Economic Events)

कृषि निर्यात नीति-2018

चर्चा में क्यों?

- 6 दिसंबर, 2018 को केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि निर्यात नीति को मंज़ूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब डॉलर तक पहुँचाना है।
- इस नीति के तहत प्रमुख रूप से चाय, कॉफी तथा चावल इत्यादि कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नवीन कृषि नीति से विश्व के कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में भी वृद्धि होगी।
- इस नीति की निगरानी और क्रियान्वयन के लिये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक निगरानी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

कृषि निर्यात नीति के मुख्य उद्देश्य

- 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2022 तक 60 अरब डॉलर करना तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुँचाना।
- निर्यात किये जाने वाले कृषि उत्पादों में विविधता लाना तथा उनके लिये नए बाज़ार तलाशना और इसके साथ ही शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों सहित अन्य किस्म के कृषि उत्पादों को विभिन्न तरीके से इस्तेमाल करने लायक बनाकर उनका मूल्य संवर्द्धन करना।
- स्वदेशी, नवीन, जैविक, स्थानीय प्रजाति, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
- कृषि उत्पादों के लिये बाज़ार पहुँच को आसान बनाने के लिये एक संस्थागत प्रणाली विकसित करना तथा इनके व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना और इनसे जुड़े पादप-स्वच्छता के मामलों को निपटाना।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़कर कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर जल्द ही दोगुना करना।
- घरेलू किसानों को वैश्विक बाज़ारों में निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना।
- कृषि निर्यात नीति में रणनीति और संचालन पर विशेष ज़ोर देना। रणनीतिक उपायों के तहत ढाँचागत और लॉजिस्टिक सुविधाओं का निर्माण करना, कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाना, कृषि उत्पादों के लिये क्लस्टर विकास करना और ब्रांड इंडिया की मार्केटिंग आदि को बढ़ावा देना।
- कृषि निर्यात नीति के तहत उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना, कड़े गुणवत्ता मानक स्थापित करना एवं अनुसंधान और विकास जैसे संचालन उपाय पर ज़ोर देना।

गंगा नदी पर देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर वाराणसी में निर्मित भारत के पहले मल्टीमॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया तथा इस मौके पर इस अंतर्देशीय जलमार्ग पर कोलकाता से 30 अक्तूबर भेजे गए पहले कार्गो की भी उन्होंने अगवानी की।

प्रमुख बिंदु

- वाराणसी स्थित टर्मिनल गंगा नदी पर बनने वाले 3 मल्टी मॉडल तथा 2 इंटर मॉडल टर्मिनल्स की श्रृंखला में पहला है।
- इन टर्मिनल्स का निर्माण भारत सरकार की 'जलमार्ग विकास परियोजना' के तहत किया जा रहा है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग क्र.1 के 'हल्दिया-वाराणसी खंड' को बड़े जहाज़ों के परिवहन के लिये विकसित करना तथा इस प्रकार अंतर्देशीय जलमार्ग को सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के साधन के रूप में प्रोत्साहित करना है।
- जलमार्ग विकास परियोजना 'भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जो कि भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।
- जलमार्ग विकास परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जा रही है तथा भारत सरकार व विश्व बैंक की परियोजना में भागीदारी 50 : 50 के अनुपात में है।

स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 दिसंबर, 2018 को गोवा में किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा गोवा सरकार द्वारा किया गया।

मुख्य बिंदु

- इस शिखर सम्मेलन की थीम 'भारत में नवाचार के लिये वैश्विक पूंजी जुटाना (Mobilizing Global Capital for Innovation in India)' थी ।
- इसमें विभिन्न देशों के लगभग 150 प्रतिभागियों व निवेशकों ने हिस्सा लिया।

3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (International Events)

जी-20 शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2018 के मध्य जी-20 का 13वाँ शिखर सम्मेलन ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉओरिसियो माकरी (Mauricio Macri) ने की। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन में बदलते वैश्विक परिदृश्य में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने, रोज़गार उपलब्धता एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ज़ोर दिया गया।
- इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य दोनों देशों के बीच व्यापार-वाणिज्य संबंधी तनावों को कम किये जाने पर चर्चा की गई
- सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य त्रिपक्षीय वार्त्ता हुई। इस वार्त्ता में तीनों देशों के नेताओं ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिये सहमति व्यक्त की।
- इस सम्मेलन के दौरान 30 नवंबर, 2018 को ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक वार्षिक बैठक भी संपन्न हुई।
- इस शिखर सम्मेलन में शक्तिकांत दास ने भारत के शेरपा के रूप में कार्य किया।

जी-20 के बारे में

- जी-20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों में विचार-विमर्श के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है। इसमें 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- जी-20 ग्रुप के सभी सदस्य समग्र रूप से विश्व की जनसंख्या का दो-तिहाई, विश्व जी.डी.पी. का लगभग 85% तथा विश्व व्यापार के लगभग 75% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी स्थापना 'पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट' के बाद वर्ष 1999 में हुई थी।
- वर्ष 2008 में आए वैश्विक आर्थिक संकट के बाद 2008 से जी-20 के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक प्रारंभ हुई। जी-20 का 14वाँ शिखर सम्मेलन ओसाका, जापान में प्रस्तावित है। वर्ष 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा।

यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन

चर्चा में क्यों?

10 और 11 दिसंबर को मोरक्को के मराकेश नगर में 'यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन' का अंतर-सरकारी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 164 देशों द्वारा 'ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेग्युलर माइग्रेशन' को अंगीकृत किया गया। यह विश्वभर में लगभग 26 करोड़ प्रवासियों को एक सुरक्षित व गरिमामयी जीवन प्रदान करने संबंधी ब्लू प्रिंट है।

यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन के बारे में

यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में चलाई जा रही एक अंतरसरकारी समझौता वार्त्ता है।

उपर्युक्त संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2016 में शरणार्थियों और प्रवासियों के लिये न्यूयॉर्क घोषणापत्र अपनाया गया था। इस घोषणा के तहत हस्ताक्षरकर्त्ता देशों ने शरणार्थियों एवं प्रवासियों के सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिये वैश्विक कॉम्पैक्ट तंत्र विकसित करने का निर्णय लिया था। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवजन के प्रशासन में सुधार करना, वर्तमान वैश्विक प्रवजन की चुनौतियों का समाधान करना है।

मुख्य लक्ष्य

- प्रवासियों की मेज़बान देशों में विधिक व कानूनी स्थिति की परवाह किये बिना उनकी सुरक्षा, गरिमा और मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- उनका पुनर्वास करना एवं मेज़बान देशों में उन्हें शिक्षा और नौकरियों तक पहुँच प्रदान करना।
- बड़ी संख्या में शरणार्थियों और प्रवासियों को शरण देने वाले देशों की सहायता करना।
- प्रवासियों की ज़रूरतों और क्षमताओं को समझना एवं मेज़बान देशों के समाज के साथ उनके सम्मिलन के लिये योजनाओं का खाका तैयार करना।
- प्रवासियों को मानवीय और विकास सहायता उपलब्ध कराना।
- प्रवासियों के प्रति मेज़बान देशों के नागरिकों में घृणा, नस्लीय व जातीय भेदभाव को दूर करना।
- असुरक्षित व संकटपूर्ण परिस्थितियों में फँसे प्रवासियों के बचाव के लिये विभिन्न राष्ट्रों की अगुआई में गैर-बाध्यकारी व स्वैच्छिक दिशानिर्देश तैयार करना।

4

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
(Science and Technology)

GSAT-11 का सफल प्रक्षेपण

चर्चा में क्यों?

5 दिसंबर, 2018 को फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू प्रक्षेपण केंद्र से इसरो द्वारा निर्मित GSAT-11 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- GSAT-11 भारत का नेक्स्ट जेनरेशन उच्च कार्यक्षमता युक्त संचार उपग्रह है, इसे एरियन-5 VA-246 प्रक्षेपण यान की सहायता से प्रक्षेपित किया गया।
- GSAT-11 का प्रमोचन भार 5854 किग्रा., शक्ति 13.6 किलोवाट तथा अभियान की कालावधि 15 वर्ष है। यह इसरो द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी उपग्रह है।
- GSAT-11को एरियन-5 द्वारा भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया था, जिसके बाद कर्नाटक के हसन में स्थित इसरो की 'मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी' ने अभियान का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया।
- GSAT-11 उन्नत संचार उपग्रहों की शृंखला में अग्रणी है। मल्टी-स्पॉट बीम एंटीना युक्त GSAT-11 भारत की संपूर्ण मुख्य भूमि तथा सभी द्वीपों पर कवरेज रखेगा।
- GSAT-11 देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध कराने तथा नई पीढ़ी के अनुप्रयोगों के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

PSLV-C43 / हाइसिस (HysIS) अभियान

चर्चा में क्यों?

29 नवंबर, 2018 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV–C43 की सहायता से भारत के 'हाइपर इमेजिंग स्पेक्ट्रल सैटेलाइट (HysIS)' सहित 30 अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयात्री उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- PSLV–C43, PSLV का 'कोर अलोन' संस्करण है।
- इस अभियान का प्राथमिक उपग्रह 'हाइसिस' 380 किग्रा. भार वाला एक 'भू-अवलोकन उपग्रह' है जिसका प्रमुख लक्ष्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम के 'दृश्य (Visible)', 'नियर इंफ्रारेड' व 'शॉर्ट इंफ्रारेड' क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है।
- PSLV–C43 अभियान में हाइसिस के अतिरिक्त 8 देशों के 29 नैनो उपग्रह तथा 1 माइक्रो उपग्रह भी प्रक्षेपित किये गए थे जो कि इसरो की विपणन इकाई 'एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के साथ वाणिज्यिक रूप से अनुबंधित थे।
- यह PSLV की सहायता से किया गया 45वाँ प्रक्षेपण था।

नासा OSIRIS-REx स्पेसक्राफ्ट

चर्चा में क्यों?

दिसंबर में, नासा का OSIRIS-REx स्पेसक्राफ्ट दो वर्षों की यात्रा के बाद बेन्नु क्षुद्रग्रह पर पहुँच गया है। OSIRIS-REx, Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer का संक्षिप्त रूप है।

प्रमुख बिंदु

- यह स्पेसक्राफ्ट बेन्नु से धूल इत्यादि के नमूने लेकर वापस लौटेगा। इसकी सहायता से बेन्नु क्षुद्रग्रह के आकार, धरातल तथा वातावरण का अध्ययन किया जाएगा।
- OSIRIS-REx मिशन को सितंबर, 2016 में बेन्नु क्षुद्रग्रह के अध्ययन के लिये प्रक्षेपित किया गया था। OSIRIS-REx मिशन 2023 में क्षुद्रग्रह से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौटेगा। इन नमूनों से क्षुद्रग्रहों की उत्पत्ति व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उपयोगी जानकारी मिल सकेगी।

साइबर-फिज़िकल प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन

चर्चा में क्यों?

6 दिसंबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर-फिज़िकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन (एनएम-आईसीपीएस) को मंज़ूरी दे दी। इस मिशन के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को ₹ 3600 करोड़ की धनराशि अगले पाँच वर्षों के लिये आवंटित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस मिशन के तहत समाज की बढ़ती प्रौद्योगिकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये अग्रणी देशों के अंतर्राष्ट्रीय रुझानों तथा रोडमैप का अध्ययन किया जाएगा।
- इस मिशन के तहत निम्नलिखित विकास और कार्य किये जाएंगे–
  - देश में साइबर-फिज़िकल प्रणालियों (सीपीएस) और संबंधित प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता सुगम हो जाएगी।

5 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
(Environment and Ecology)

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन-2018

चर्चा में क्यों ?

- 2 से 14 दिसंबर, 2018 के मध्य पोलैंड के कैटोवाइस शहर में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज-कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज-COP-24 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल सदस्यों का सम्मेलन (CMP 14) भी COP24 के साथ-साथ कैटोवाइस में ही आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा किया गया।
- इस शिखर सम्मेलन में वर्ष 2015 में किये गए पेरिस समझौते के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस शिखर सम्मलेन की अध्यक्षता पोलैंड के पर्यावरण मंत्री माइकल कुर्तिका द्वारा की गई।
- ज्ञातव्य है कि पेरिस जलवायु समझौते में शामिल विभिन्न देशों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 21वीं सदी के अंत तक विश्व के औसत तापमान में औद्योगीकरण के पूर्व के वैश्विक तापमान के स्तर से 2°C से अधिक की वृद्धि नहीं होने दी जाएगी और सदस्यों द्वारा यह प्रयास भी किया जाएगा कि वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखा जाए।

COP24·KATOWICE 2018
UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE

जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में लिये गए प्रमुख निर्णय

- इस शिखर सम्मेलन में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली (Rulebook) का मसौदा तैयार किया गया। शिखर सम्मलेन में शामिल 200 देशों के प्रतिनिधियों ने इन नियमों पर सहमति व्यक्त की है। ये नियम, वर्ष 2020 से पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के क्रियान्वयन के लिये आधार का कार्य करेंगे।
- इस नियमों के तहत विकसित देश, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिये वित्त की उपलब्धता में पारदर्शिता बनाए रखेंगे।
- ज्ञातव्य है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिये विकसित देश, विकासशील देशों को ग्रीन क्लाइमेट फंड के माध्यम से प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर प्रदान करेंगे।
- इन नियमों में यह भी निर्धारित किया गया है कि विभिन्न देश किस प्रकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, शमन और अनुकूलन के उपायों को अपनाएंगे, साथ ही अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
- ये नियम, शिखर सम्मेलन में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन लेखांकन और कार्बन कटौती की गणना करने में अधिक स्पष्टता प्रदान करेंगे।
- इस शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की एक समान रूप से गणना के तरीके पर सहमति व्यक्त की है। जिसके तहत यदि अल्प विकसित देशों को लगता है कि वे निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वे इस संबंध में अपनी क्षमता के अनुरूप योजना पेश कर सकते हैं।
- इस शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने वर्ष 2023 में जलवायु कार्रवाई (Climate Action) की प्रभावशीलता का आकलन करने एवं प्रौद्योगिकी के विकास और हस्तांतरण पर प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट करने के तरीके पर सहमति व्यक्त की है।
- हालाँकि, भारत समेत कई देशों द्वारा इस नियमावली के प्रति यह कहकर संदेह व्यक्त किया गया है कि ये नियम जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या के निदान के लिये आवश्यक शीघ्रता पर बल नहीं देते हैं।

पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के बारे में

- पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, अनुकूलन और लागत का वित्तीय प्रबंधन करने के लिये 'यूएनएफसीसीसी के सदस्यों' (Parties of UNFCCC) द्वारा किया गया समझौता है।
- इस समझौते के तहत 21वीं सदी के अंत तक विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से कम पर सीमित रखना है। इसके साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि औसत वैश्विक तापमान 1.5°C तक ही सीमित रहे। इसके लिये कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2050 तक 50% की कमी और वर्ष 2100 तक 100% तक की कटौती का लक्ष्य रखा गया है।

6 सुरक्षा (Security)

एविया इंद्र-18 (भारत)

चर्चा में क्यों?

भारत और रूस की वायुसेनाओं के बीच एविया इंद्र 18 नामक संयुक्त अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में 10 से 21 दिसंबर के बीच किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रथम एविया इंद्र का आयोजन 2014 में किया गया था।
- एविया इंद्र 2018 भारतीय वायु सेना एवं रशियन फेडेरेशन एयरोस्पेस फोर्स के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास की शृंखला में दूसरा अभ्यास था, इसकी योजना दो चरणों में बनाई गई थी।
- यह एक अनूठा अभ्यास है जिसमें विदेशी प्रतिभागी अपनी वायु परिसंपत्तियाँ नहीं लाता। रूस में भारतीय वायु सेना के पायलटों ने 17 सितंबर, 2018 से 28 सितंबर, 2018 तक लिपेट्स्क में रूसी वायुसेना के वायुयान में रूसी पायलटों के साथ उड़ान भरी थी। भारत में रूसी वायुसेना के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के विमानों में उड़ान भरी।

इंद्र नेवी-2018

चर्चा में क्यों?

9–16 दिसंबर, 2018 के मध्य भारत व रूस की नौसेनाओं के मध्य 'इंद्र नेवी 2018' युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- विशाखापत्तनम में आयोजित इस युद्धाभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य अंतर-संचालनीयता (Inter- operability) को बढ़ावा देना तथा समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में साझी समझ व प्रक्रियाएँ विकसित करना रहा।
- भारतीय नौसेना की ओर से युद्धाभ्यास में निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर 'आईएनएस रणवीर', स्वदेश निर्मित फ्रिगेट 'आईएनएस सतपुड़ा', एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) कॉर्वेट 'आईएनएस कदमत', दो मिसाइल कॉर्वेट 'आईएनएस कुठार' व 'आईएनएस खंजर' एवं एक फ्लीट टैंकर 'आईएनएस ज्योति' ने भाग लिया।
- इनके साथ एक 'सिंधुघोष क्लास पनडुब्बी' तथा एक समुद्री गश्त एयरक्राफ्ट 'डॉर्नियर' भी इस युद्धाभ्यास में सम्मिलित हुए।
- रूस की ओर से इस अभ्यास में रशियन फेडरेशन नेवी (RuFN)' के 'वार्याग', 'एडमिरल पेन्तेलयेव' तथा 'बोरिस बुतोमा' जहाज़ ने भाग लिया।
- उल्लेखनीय है कि यह इस युद्धाभ्यास का 10वाँ आयोजन था, जबकि पहली बार यह युद्धाभ्यास 2003 में आयोजित किया गया था।

हैंड-इन-हैंड 2018

चर्चा में क्यों?

चीन के चेंगडू में भारत व चीन की थल सेनाओं के बीच 10–23 दिसंबर, 2018 की अवधि में हैंड-इन-हैंड युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस युद्धाभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य संबंधों का संवर्द्धन करना तथा यूएन अधिदेश के अंतर्गत आतंकवाद-निरोधी वातावरण में रणनीतिक स्तर के ऑपरेशंस अभ्यास में सम्मिलित रहना रहा।
- अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सेना की 11वीं सिख लाइट इन्फैंट्री तथा चीनी सेना का प्रतिनिधित्व 'तिब्बती मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट' की एक इकाई के सैनिकों ने किया।
- युद्धाभ्यास की औपचारिक शुरुआत 11 दिसंबर, 2018 को हुई।

शिन्यु मैत्री-2018

चर्चा में क्यों?

3 दिसंबर, 2018 को भारतीय वायुसेना और जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेज (Japanese Air Self Defence Forces – JASDF) के बीच 'शिन्यु मैत्री' (SHINYUU Maitri) नामक अभ्यास शुरू हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस युद्धाभ्यास का आयोजन आगरा (उत्तर प्रदेश) में किया गया।
- इस युद्ध अभ्यास की थीम 'परिवहन वायुयान पर संयुक्त गतिशीलता/मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief–HADR)' है।
- भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच यह पहला अभ्यास है।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच भारत में मिज़ोरम में 'धर्म गार्जियन-2018' नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया गया था।

7 रिपोर्ट एवं सूचकांक (Reports and Indices)

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2019

चर्चा में क्यों?

दिसंबर 2018 में जर्मनवाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टिट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से 'जलवायु प्रदर्शन सूचकांक-2019' प्रकाशित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 2019 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 11वाँ स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत को इस सूचकांक में 14वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
- हालाँकि इस रिपोर्ट में कोयला परियोजनाओं के कारण भारत की स्वच्छ ऊर्जा की प्रगति पर प्रभाव पड़ने के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई है।
- पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी शीर्ष तीन रैंक में किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी देश ने सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया है।
- इस सूचकांक में 56 देशों तथा यूरोपीय संघ को आकलन में शामिल किया गया था, जिनमें चौथा स्थान स्वीडन को, पाँचवा स्थान मोरक्को को तथा छठा स्थान लिथुआनिया को प्राप्त हुआ । अंतिम पाँच स्थानों पर क्रमशः सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, कोरिया तथा चीनी ताइपे रहे।
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2019 की रिपोर्ट को 24वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP 24) के दौरान जारी किया गया।
- इस सूचकांक में 4 श्रेणियों (ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग तथा जलवायु नीति) के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2018

चर्चा में क्यों?

दिसंबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2018 जारी की गई, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 'औसत से कम लंबाई वाले (stunted)' सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में ही हैं।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 150.8 मिलियन बच्चे औसत से कम लंबाई वाले, लगभग 50.5 मिलियन बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वज़न वाले (wasted) तथा लगभग 38.3 मिलियन बच्चे अति-वज़नी (overweight) हैं।
- भारत में उचित पोषण प्राप्त न होने के कारण 46.6 मिलियन बच्चे औसत से कम लंबाई वाले (stunted) हैं जो कि विश्व में सर्वाधिक हैं।
- भारत में विभिन्न ज़िलों में बच्चों में बौनेपन (stunting) की दरें अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में यह सर्वाधिक 65.1 प्रतिशत है। बौनेपन की सर्वाधिक दर वाले देश के शीर्ष दस ज़िलों में से छः ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं।
- बौनेपन और लंबाई के अनुपात में कम वज़न के संदर्भ में जनजातीय समुदायों के बच्चों की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक है।
- भारत में लगभग 40 प्रतिशत बच्चे बौनेपन की समस्या से ग्रस्त हैं, जो कि 21 प्रतिशत के वैश्विक औसत से काफी अधिक है और भारत में पोषण की बदहाल स्थिति की तरफ संकेत करता है।

डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट-2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' (DBR 2019) जारी की। भारत ने DBR-2019 के 'व्यापार सुगमता सूचकांक' (Ease of Doing Business) में अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए 23 पायदान की छलाँग लगाई है।

प्रमुख बिंदु

- 'डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट' के अनुसार, 2 जून, 2017 से 1 मई, 2018 के बीच रिकॉर्ड 314 नियामक सुधार हुए। दुनिया भर में 128 अर्थव्यवस्थाओं ने पर्याप्त विनियामक सुधार प्रस्तुत किये जिससे डूइंग बिजनेस द्वारा मापन में शामिल सभी क्षेत्रों में व्यवसाय करना आसान हो गया है।
- डूइंग बिज़नेस 2019 में सबसे उल्लेखनीय सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ अफगानिस्तान, जिबूती, चीन, अज़रबैजान, भारत, टोगो, केन्या, कोट डी आईवर (आइवरी कोस्ट), तुर्की और रवांडा हैं।
- ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस संघ, भारत और चीन में कुल 21 सुधार हुए।
- व्यापार सुगमता सूचकांक की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएँ विनियामक दक्षता और गुणवत्ता की सामान्य विशेषताओं को साझा करती हैं, जिनमें निर्माण के दौरान अनिवार्य निरीक्षण, बिजली कटौती के दौरान सेवा बहाल करने के लिये स्वचालित उपकरणों का उपयोग, दिवालिया कार्यवाही में लेनदारों के लिये मज़बूत सुरक्षा उपायों की उपलब्धता और स्वचालित विशेषीकृत वाणिज्यिक अदालतें शामिल हैं।

8 सामाजिक मुद्दे
(Social Issues)

लिंगायत संप्रदाय

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि उसने पहले ही राज्य सरकार को सूचित किया था कि लिंगायत/वीरशैव समुदाय को अल्पसंख्यक धर्म की स्थिति प्रदान करने हेतु राज्य की सिफारिशों को मानना संभव नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अदालत के समक्ष 13 नवंबर, 2018 को राज्य सरकार को भेजे गए पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपनी पूर्ववत स्थिति को दोहराया कि लिंगायत/वीरशैव समुदाय को 'हिंदुओं के एक धार्मिक संप्रदाय' के रूप में ही मान्यता दी जाती है।
- लिंगायतों/वीरशैवों को अल्पसंख्यक धर्म की स्थिति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार और कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग (KSMC) द्वारा किये गए कार्यों पर पूछताछ संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह पत्र कर्नाटक उच्च न्यायालय में जमा किया गया था।
- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से परामर्श के बाद राज्य को लिखा, "लिंगायत और वीरशैवों द्वारा अलग स्थिति की मांग पर पहले भी विचार किया गया है और यह देखा गया था कि 1872 की जनगणना (भारत में पहली आधिकारिक जनगणना) के बाद से लिंगायत को हमेशा हिंदू धर्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा लिंगायत को हिंदू धर्म के धार्मिक संप्रदाय के रूप में माना जाता है।"
- गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को उद्धृत करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा, "अगर लिंगायत/वीरशैव को हिंदू के अलावा अलग संहिता प्रदान करके एक अलग धर्म के रूप में माना जाए, तो निर्धारित धर्म का दावा करने वाले अनुसूचित जाति (SC) के सभी सदस्य अनुसूचित जाति के रूप में प्राप्त अपने सभी लाभों के साथ अनुसूचित जाति के रूप में अपनी स्थिति खो देंगे।"
- स्मरणीय है कि 23 मार्च, 2018 को कर्नाटक राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा 2(ब) के तहत बासवन्ना के दर्शन और शिक्षाओं का पालन करने वाले लिंगायतों तथा वीरशैवों को एक धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिये केंद्र से सिफारिश की थी।

लिंगायत समुदाय के बारे में

- बारहवीं सदी में कर्नाटक में 'बासवन्ना' (1106 - 1168 ई.) के नेतृत्व में एक धार्मिक आंदोलन चला। बासवन्ना कलचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। बासवन्ना के अनुयायी लिंगायत (लिंग धारण करने वाले) व वीरशैव (शिव के वीर) कहलाए।
- इन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर समाज के वर्गीकरण की पैरवी की। लिंगायत, मृतकों को जलाने की बजाय दफनाते हैं तथा श्राद्ध नियमों का पालन नहीं करते, न तो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को मानते हैं और न ही पुनर्जन्म को। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद वे शिव में ही लीन हो जाएंगे और पुनः इस लौकिक संसार में वापस नहीं लौटेंगे। लिंगायत मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं।
- यह माना जाता है कि वीरशैव तथा लिंगायत एक ही हैं किंतु लिंगायतों का तर्क है कि वीरशैवों का अस्तित्व लिंगायतों से पहले से है तथा वीरशैव मूर्तिपूजक हैं। वीरशैव वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जबकि लिंगायत ऐसा नहीं करते।
- कर्नाटक में लगभग 18 प्रतिशत आबादी लिंगायतों की है। ये लंबे समय से हिंदू धर्म से पृथक् धर्म का दर्जा चाहते हैं। अगर इन्हें धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो इन्हें भी अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिये चलाए जाने वाले कार्यक्रमों व योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

नॉर्थ सेंटीनल द्वीप एवं भारत की संरक्षित जनजातियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जॉन ऐलेन चाऊ नामक एक अमेरिकी धर्म प्रचारक की अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में स्थित नॉर्थ सेंटीनल द्वीप पर सेंटीनलीज़ जनजाति द्वारा हत्या कर दी जाने की घटना सामने आई है।

क्या है घटना?

- 17 नवंबर को उत्तरी सेंटीनल द्वीप के निकट एक तट पर एक शव देखा गया, जिसकी पहचान अमेरिकी नागरिक 'जॉन ऐलेन चाऊ' के रूप में की गई।
- माना जा रहा है कि उत्तरी सेंटीनल द्वीप पर निवास करने वाली सेंटीनलीज़ जनजाति ने आत्मरक्षा में चाऊ की हत्या कर दी।
- उल्लेखनीय है कि मृतक ने उक्त द्वीप पर गैर-कानूनी तरीके से पहुँचने का प्रयास किया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब्स (विनियम), 1956 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत उत्तरी सेंटीनल द्वीप पर आवागमन प्रतिबंधित है।

9 कला एवं संस्कृति
(Art and Culture)

कालीन नगरी भदोही को मिला 'एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' (Export Excellence) का दर्जा

चर्चा में क्यों?

पूरी दुनिया में हाथ से बने कालीनों के लिये मशहूर उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले को 'एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' (Export Excellence) का टैग प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

भदोही को 'टाउंस ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' मिलने के बाद शहर के कालीन निर्माताओं को आधुनिक मशीनों को खरीदने, बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करने हेतु दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन के लिये केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।

भदोही को यह दर्जा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत विदेश व्यापार निदेशालय (Directorate General of Foreign Trade - DGFT) ने प्रदान किया है।

गंगा के किनारे स्थित यह छोटा-सा शहर DGFT द्वारा यह दर्जा प्राप्त करने वाला 37 वाँ शहर है।

यह दर्जा प्राप्त करने वाले अन्य शहरों में तिरुपुर, लुधियाना, कनूर, करूर, देवास, इंदौर, भीलवाड़ा, सूरत, कानपुर, अम्बर, जयपुर और श्रीनगर शामिल हैं।

विदेश व्यापार निदेशालय (DGFT)

- विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जिसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशक करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिये ज़िम्मेदार है।

हॉर्नबिल महोत्सव

चर्चा में क्यों?

नगालैंड राज्य के स्थापना दिवस (1 दिसंबर, 1963) के अवसर पर हर साल हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार राज्य में 19वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह सांस्कृतिक महोत्सव नृत्य, संगीत और भोजन के साथ-साथ वर्षों से अपनाई गई नगा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का कलात्मक प्रदर्शन है, जो कि नगा समाज की विविधताओं को प्रदर्शित करता है।
- इस महोत्सव का उद्देश्य नगालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करने तथा सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ इसकी परंपराओं को प्रदर्शित करना है।
- इस उत्सव का आयोजन राज्य के पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- पहली बार इस उत्सव का आयोजन वर्ष 2000 में किया गया था।

नगालैंड के बारे में

- नगालैंड राज्य का गठन औपचारिक रूप से 1 दिसंबर, 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में किया गया था। यह पश्चिम में असम, पूर्व मे म्याँमार (बर्मा), उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्से तथा दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है।
- इसकी राजधानी कोहिमा है। राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी (English) है।
- राज्य में 16 प्रमुख जनजातियाँ तथा उनकी उप-जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति रिवाज, भाषा और पोशाक के मामले में एक-दूसरे से भिन्न है।

प्रसाद योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में गंगोत्री व यमुनोत्री (उत्तराखंड), अमरकंटक (मध्य प्रदेश), पारसनाथ (झारखण्ड) को प्रसाद योजना (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive) में शामिल किया है। इसके पश्चात् प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किये गए स्थानों की संख्या बढ़कर 41 पर पहुँच गई है।

प्रमुख बिंदु

- प्रसाद योजना को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में आरंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों का विकास योजनाबद्ध तरीके से करना है। धार्मिक स्थलों के पर्यटन स्थलों के रूप में विकास से इन क्षेत्रों के स्थानीय समुदाय के लिये रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस योजना के तहत स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प तथा भोजन इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।

10 खेल घटनाक्रम
(Sports Events)

फुटबॉल

प्रतियोगिता का नाम	आयोजन स्थल	विजेता	उपविजेता
इंटरकॉन्टिनेंटल कप, 2018	मुंबई	भारत	केन्या
सैफ सुजुकी कप, 2018	ढाका, बांग्लादेश	मालदीव	भारत
फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप, 2018	फ्राँस	जापान	स्पेन
यूएफा चैंपियंस लीग, 2017-18	कीव, यूक्रेन	रियल मैड्रिड	लिवरपूल
संतोष ट्रॉफी 2017-18	पश्चिम बंगाल	केरल	पश्चिम बंगाल
इंडियन सुपर लीग, 2017-18	भारत	चेन्नइयन एफसी	बंगलूरू एफसी

फीफा फुटबॉल विश्व कप - 2018

विजेता –	फ्राँस	*उपविजेता* –	क्रोएशिया
गोल्डन बॉल अवार्ड	–	लुका मॉड्रिक (क्रोएशिया)	
गोल्डन बूट अवार्ड	–	हैरी केन (इंग्लैंड)	
गोल्डन ग्लव अवार्ड	–	थैबॉट कोर्टोइस (बेल्जियम)	
फीफा यंग प्लेयर अवार्ड	–	किलियन मबापे (फ्राँस)	
फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी	–	स्पेन	

स्मरणीय तथ्य

- 14 जून से 15 जुलाई, 2018 के मध्य 21वें फीफा फुटबाल विश्व कप-2018 का आयोजन रूस में किया गया।
- 15 जुलाई को मॉस्को के लुज़्निकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में फ्राँस ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा कर दूसरी बार विश्व कप जीत लिया। इससे पूर्व वर्ष 1998 में फ्राँस ने विश्व कप जीता था।
- प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में फ्राँस के एंटोनी ग्रीजमैन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिये मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान किया गया।
- इस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान बेल्जियम ने इंग्लैंड को 2-0 से हरा कर हासिल किया।
- टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड क्रोएशिया के लुका मॉड्रिक को प्रदान किया गया।
- टूर्नामेंट में सर्वाधिक 6 गोल करने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी केन को गोल्डन बूट अवार्ड प्रदान किया गया।
- टूर्नामेंट में सर्वाधिक 27 गोलों का बचाव करने के लिये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का गोल्डन ग्लव अवार्ड बेल्जियम के थैबॉट कोर्टोइस को प्रदान किया गया।
- फीफा फुटबाल विश्व कप-2018 का शुभंकर जाबिवाका (Zabivaka) नामक यूरेशियन भेड़िये को बनाया गया था।
- 'लिव इट अप' (Live It Up) गीत को फीफा फुटबाल विश्व कप-2018 का आधिकारिक गीत बनाया गया था।
- एडिडास कंपनी द्वारा बनाई गई 'टेलस्टार 18' बॉल को फीफा फुटबाल विश्व कप-2018 की आधिकारिक गेंद के रूप में प्रयुक्त किया गया था।
- फीफा फुटबॉल विश्व कप के इस संस्करण में कुल 32 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें से पनामा और आइसलैंड दो ऐसे देश थे जिन्होंने पहली बार फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लिया।

क्रिकेट

प्रतियोगिता का नाम	आयोजन स्थल	विजेता	उपविजेता	प्लेयर ऑफ द सीरीज़/टूर्नामेंट
ICC महिला टी-20 विश्वकप-2018	वेस्टइंडीज	ऑस्ट्रेलिया	इंग्लैंड	एलिसा हीली
दलीप ट्रॉफी, 2018–19	डिंडीगुल (तमिलनाडु)	इंडिया ब्लू	इंडिया रेड	
महिला एशिया कप टी-20 टूर्नामेंट–2018	मलेशिया	बांग्लादेश	भारत	हरमनप्रीत कौर

11 विविध
(Miscellaneous)

चर्चित व्यक्ति

नियुक्ति

कल्वकुंतल चंद्रशेखर राव

- 13 दिसंबर, 2018 को तेलंगाना के राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिम्हन ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- ज्ञातव्य है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति को 119 में से 88 सीटें प्राप्त हुईं। के. चंद्रशेखर राव वर्ष 2014 में गठित तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तेलंगाना का गठन 2 जून, 2014 को किया गया था। के. चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति नामक राजनीतिक पार्टी के संस्थापक हैं।

जोरमथंगा

- 15 दिसंबर, 2018 को मिज़ोरम के राज्यपाल कुम्मानम राजशेखरन ने मिज़ो नेशनल फ्रंट (Mizo National Front) के अध्यक्ष जोरमथंगा को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- ज्ञातव्य है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में मिज़ोरम की 40 विधानसभा सीटों में उनकी पार्टी को 26 सीटों पर जीत मिली थी। वे दिसंबर, 1998 से दिसंबर, 2008 तक दो बार मिज़ोरम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
- ज्ञातव्य है कि मिज़ो नेशनल फ्रंट की स्थापना लालदेंगा ने 1961 में की थी। प्रारंभ में यह एक अलगाववादी संगठन था। वर्ष 1986 में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने भारत सरकार के साथ 'मिज़ो समझौते' पर हस्ताक्षर किये और अलगाववाद का मार्ग छोड़ कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना शुरू किया था।

भारत भूषण व्यास

- 13 दिसंबर, 2018 को भारत भूषण व्यास ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलवाई। इससे पूर्व वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार के पद पर कार्यरत थे।
- स्मरणीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो, तक होता है।
- संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति और पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यालय की अवधि से संबंधित है।

कमल नाथ

- 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमल नाथ को प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- कमल नाथ भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस से संबंध रखते हैं तथा वर्तमान लोकसभा में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वर्तमान लोकसभा (16वीं लोकसभा) के प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं।
- ये छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा के लिये चुने गए हैं।
- ये विभिन्न सरकारों में वाणिज्य व उद्योग मंत्री, पर्यावरण राज्यमंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री जैसे महत्त्वपूर्ण पद सँभाल चुके हैं।

अशोक गहलोत

- 17 दिसंबर को राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के नेता अशोक गहलोत को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- गहलोत राजस्थान के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले वे 1998 से 2003 तक तथा 2008 से 2013 तक यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2018 में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में वे जोधपुर ज़िले की सरदारपुरा विधानसभा से विधायक चुने गए।

दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
(Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(32 + 10 Booklets) (₹15,500/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(32 Booklets) (₹14,000/-)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(34 बुकलेट्स) ₹10,500/-

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 Booklets) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 Booklets) (₹10,000/-)

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 Booklets) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 Booklets) (₹10,000/-)

For UPPCS Mains (in English Medium)

Self Learning Module

19 GS + 1 Essay + 1 Compulsory Hindi Booklets
₹7000/-

Offer

Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine for comprehensive coverage of current affairs

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

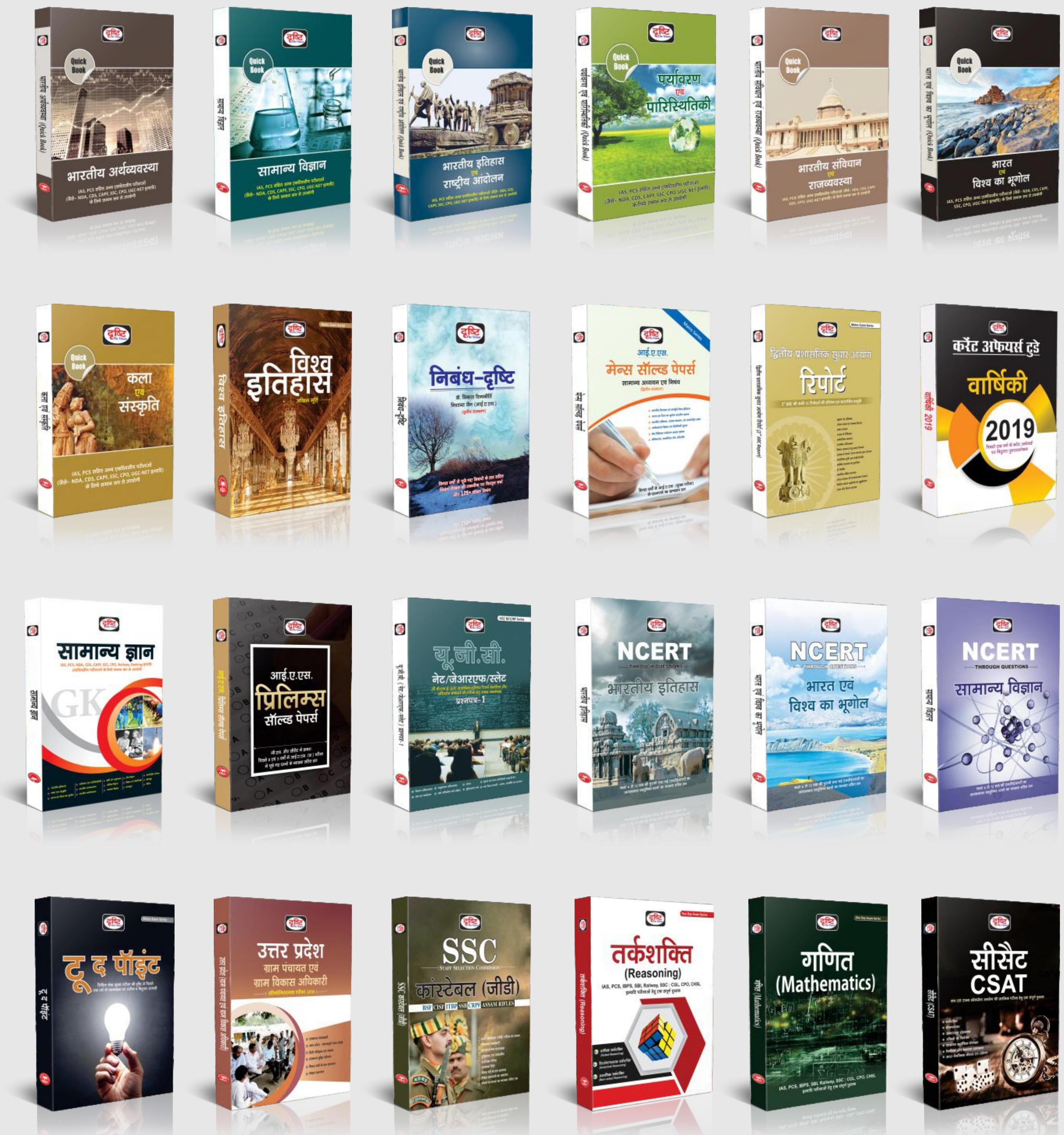

Drishti Publications

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-939175-2-7

मूल्य : ₹ 200